गोरखधंधा...बनी हुई सड़कों को बनाएगा एफएमडीए

मुख्यमंत्री खट्टर से अफसरों ने फर्जी और भ्रष्टाचार में लिप्त योजनाओं की घोषणाएं कराईं

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबादः मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 17 और 18 जुलाई को फरीदाबाद में थे। उन्होंने फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (एफएमडीए) की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पेयजल, जलभराव और सड़क को लेकर बात की गई और उसके बाद खट्टर ने जोर-शोर से कई घोषणाएं कर डालीं। जाहिर है कि एफएमडीए के अफसरों ने सीएम को जो बताया होगा, सीएम ने उसी के अनुसार घोषणाएं की होंगी। लेकिन इन घोषणाओं ने तमाम सरकारी विभागों की कलई खोल दी और ये भी पता चला कि प्रदेश की भाजपा सरकार कितने खोखलेपन से काम कर रही है। ताज्जुब है कि फरीदाबाद की मीडिया को मुख्यमंत्री की घोषणाओं का विश्लेषण करना जरूरी नहीं लगा। फरीदाबाद की जनता पेयजल संकट, जल भराव, टूटी और धंसी सड़कों और बिजली समस्या से बेहाल हैं लेकिन फरीदाबाद का मीडिया अफसरों और मंत्रियों की जवाबदेही तय करने से आंखें चुरा रहा है। इसीलिए एफएमडीए की बैठक के बाद की गई घोषणाओं का विश्लेषण मजदूर मोर्चा पेश कर रहा है।

दो सड़कों का गोलमाल

मुख्यमंत्री ने घोषणा की, ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ने के लिए दो प्रमुख सड़कें बनाई जाएंगी। ये सड़कें हैं - अनखीर चौक से बडखल पुल पार करते हुए, सेक्टर 28 और 19 के सामने से गुजरते हुए, सेक्टर 29 के सामने से निकल रही रोड को ग्रेटर फरीदाबाद में मंझावली से जोड़ दिया जाएगा। दूसरी सड़क है सोहना रोड से बल्लभगढ़ को पार करते हुए ग्रेटर फरीदाबाद में प्रवेश करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन सड़कों को बनाने के लिए एजेंसियां जल्द तय कर दी जाएंगी।

शहर के लोग जानते होंगे कि इन दोनों सड़कों के नाम पर कितना बड़ा झूठ अधिकारियों के कहने पर मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा है। जो नहीं जानते हैं, उन्हें हम बताते हैं। अनखीर चौक से बडखल पुल को पार करती हुई सड़क सेक्टर 28 और 19 के सामने जा रही सड़क पहले से ही बनी हुई है। इसमें रेलिंग तक लग चुकी है। सेक्टर-28 और 29 के चौराहे पर लगने वाली सब्जी मंडी का स्थान बदल दिया गया है। बीच-बीच में सड़क के एक तरफ लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर, बिल्डिंग मटीरियल डालकर अलबत्ता इस सड़क पर कब्जा कर रखा है और एक तरफ की सड़क का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसी सड़क के किनारे एक अंडरग्राउंड नाला भूड़ और बसलेवा कॉलोनी की दुकानों के साथ बनाया जा रहा है। इस सड़क के बनने से भूड़ और बसेलवा कॉलोनी में इस रोड पर बनी दुकानों के रेट इस समय सबसे महंगे हैं। इस सड़क पर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में नई समस्याएं खड़ी करेगा।

केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने इस सड़क को बनवाने में मुख्य भूमिका अदा की है। उन्हीं के चहेते ठेकेदार को इसका काम भी मिला है। डेढ़ साल पहले जब इसके बनने की शुरुआत हुई थी तो नारियल कृष्णपाल गूजर ने ही फोड़ा था। ठेकेदार ने इस सड़क पर जो रेलिंग लगाई है, अगर कोई इंजीनियर उसे देख ले तो बता देगा कि इसमें पैसे हड़पने के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। जब कभी इसकी जांच होगी, तब असलियत सामने आएगी।

अगर इस सड़क को कागजों में फिर से बनाने की बात चल रही है तो इसका मतलब ये है कि एफएमडीए के बजट का कुछ हिस्सा गलत तरीके से इस सड़क के निर्माण में दिखाया जाएगा। उस स्थिति में वह स्कैंडल का रूप लेगा। फरीदाबाद की जनता और राजनीतिक दलों को यह सवाल पूछना चाहिए कि बनी हुई सड़क को फिर से बनाने के ऐलान का गोरखधंधा क्या है।

यह सड़क निश्चित रूप से ग्रेटर फरीदाबाद ही नहीं मझावली में यमुना पर बन रहे पुल के लिए भी लाइफलाइन का काम करेगी क्योंकि यह पुल फरीदाबाद को सीधे ग्रेटर नोएडा से जोड़ेगा। जिन्हें फरीदाबाद से यमुना एक्सप्रेसवे या दादरी की तरफ जाना होगा, उनका बहुत समय बचेगा। मझावली पुल की आधारशिला सात साल पहले यानी 15 अगस्त 2014 को

एफएमडीए की बैठक में हिस्सा लेते सीएम, मंत्री और अधिकारी

खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कृष्णपाल गूजर के साथ रखी थी। कृष्णपाल दूसरी बार भी सांसद और मंत्री बन गए लेकिन मझावली पुल अभी तक शुरू नहीं हो चुका है। हालांकि अब ज्यादा काम बाकी नहीं है। बहरहाल, फरीदाबाद से मझावली तक आने वाली सड़क की हालत ग्रेटर फरीदाबाद में बहुत ही खराब है। साथ ही बीच में एक जगह घुमावदार रास्ते को भी ठीक नहीं किया गया है। नहरपार इस सड़क के दोनों तरफ धड़ल्ले से दबंग लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं। तमाम अवैध बैंक्वेट हॉल कुकुरमुत्तों की तरह उग आए हैं।

इसी तरह दूसरी सड़क जो सोहना रोड से सेक्टर 55 के सामने से बल्लभगढ़ में प्रवेश करेगी और फिर वहां से सेक्टर 76 ग्रेटर फरीदाबाद से उसे जोड़ा जाएगा। यह सड़क भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसका काफी हिस्सा बना हुआ है। यह समझ से बाहर है कि खट्टर से दोनों बनी हुई सड़कों की घोषणा नई सड़कों के नाम पर क्यों कराई गई। शहर में अधिकांश सड़कों की हालत खराब है। इनके लिए सीएम ने सिर्फ यह कहा कि इनके लिए भी बजट बनाया जाएगा। यह घोषणा गोलमोल थी यानी कोई ठोस चीज सामने नहीं आई। एफएमडीए के 6 गैर सरकारी सदस्य, जिनमें प्रॉपर्टी डीलर से लेकर उद्योगपति और डॉक्टर मुंह पर मास्क लगाए बैठे रहे और उनके मुंह से एक बार भी यह नहीं निकला कि अधिकारियों ने सीएम को गुमराह किया है। बनी-बनाई सड़कों को बनाने की घोषणा कराई जा रही है।

पेजयल पर भी नाटक

एफएमडीए की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 1 अगस्त से फरीदाबाद में 60 एमएलडी पेयजल की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। इसके लिए नगर निगम द्वारा पहले से लगाए गए 6 रैनीवैल को एफएमडीए ने शुरू करवा दिया है। इससे शहर में रैनीवैल की संख्या बढ़कर 22 हो जाएगी और पेयजल की आपूर्ति 180 एमएलडी तक पहुंच जाएगी तथा शहर को 30 प्रतिशत अतिरिक्त पानी मिलेगा। मई और जून का महीना बीतने के बाद जुलाई जब खत्म होने को है तब शहर में रैनीवेल बढ़ाए जा रहे हैं और अतिरिक्त पानी आपूर्ति का दावा किया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर सरकारी संसाधनों से पानी माफिया पानी की चोरी करवा रहा है। इसमें नेता से लेकर दबंग लोग शामिल हैं। कुछ पार्षदों के टैंकर पानी बेचने का काम कर रहे हैं। एमसीएफ के बूस्टरों से पानी की सीधी चोरी होती है। कुछ पार्षद जाकर बूस्टर पर बैठते हैं और पानी की चोरी करवाते हैं, कुछ ने अपने आरओ प्लांट लगा रखे हैं। एक पार्षद को जेई के साथ शराब की पार्टी करते बूस्टर पर लोगों ने वीडियो में देखा। मामले को पूरा ड्रामा करने के बाद दबा दिया गया। नतीजा यह निकला की अब कुछ बूस्टरों पर पुलिस निगरानी कर रही है ताकि पानी की चोरी न हो सके लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, कोई नहीं जानता। चंडीगढ़ में बैठे उच्चाधिकारियों एवं राजनेताओं की भी मिलीभगत के चलते एमसीएफ कमिश्नर गरिमा मित्तल दबंग पार्षदों, इंजीनियरिंग विंग के बेईमान अफसरों के सामने पंगु हो चुकी हैं। फरीदाबाद में पेयजल का उतना अभाव नहीं है, जितना हर बार गर्मी के दिनों में खड़ा किया जाता है। पानी के नाम पर फरीदाबाद में संगठित अपराध संचालित किया जा रहा है।

फरीदाबाद में दो महीने से भीषण जल संकट बना हुआ है। भाजपा के पार्षदों को इसके लिए सड़क पर उतरना पड़ा। यह स्थिति तब है जब केंद्रीय मंत्री गूजर का बेटा देवेन्द्र चौधरी सीनियर डिप्टी मेयर है। भाजपा पार्षद अजय बैसला अपने साथ कुछ लोगों को एमसीएफ मुख्यालय में इंजीनियरिंग विंग में घुस गया और कर्मचारियों की लगभग पिटाई की स्थिति पैदा हो गई थी। चीफ इंजीनियर, उनके मातहत इंजीनियर और जेई वगैरह दफ्तर छोड़कर भाग गए। इसके बाद एक अन्य पार्षद जयवीर खटाना ने सेक्टर 25 के बूस्टर पंप पर जनता के साथ धावा बोला। वहां उन्होंने एफएमडीए के इंजीनियर को बंधक बना लिया गया। यहां पर एफएमडीए और एमसीएफ के अफसर पेयजल संकट के लिए अलग-अलग राग अलापते रहे। सेक्टर 28 में चार दिन तक भयानक पेयजल संकट रहा। यहीं पर केंद्रीय मंत्री गूजर और उनका बेटा रहता है। देवेंद्र चौधरी को खुद साइट पर पाइप लाइन की मरम्मत के लिए जाना पड़ा। लेकिन सेक्टर 28 में कुछ पाइपलाइन में पानी होने के कारण आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों के घर पानी बराबर आता रहा, बाकी जनता परेशान रही। आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने धांधली करके कुछ पाइपलाइन को अपने घर के पास से विशेष रूप से निकाला है। फरीदाबाद के एनआईटी इलाके के सभी नेबरहुड (एनएच) में भी पानी की समस्या बनी रही। यह सब पिछले हफ्ते की ही तो बात है। लेकिन पानी के मामले में भी खट्टर को अफसरों ने गुमराह किया।

जल भराव पर वादे याद हैं

शहर में जलभराव को लेकर एमसीएफ ने बड़े-बड़े दावे किए थे। एफएमडीए ने फर्जी घोषणाएं की थीं। मॉनसून देर से आया और अभी तक जमकर बारिश भी नहीं हुई, इसके बावजूद शहर के तमाम इलाकों में जलभराव से जनता जूझ रही है। बुधवार को मौसम साफ होने के बावजूद पानी हटा नहीं। शहर के तीन अंडरपास ग्रीन फील्ड कॉलोनी, मेवला महाराजपुर और ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पास पानी से भरे हुए हैं। ओल्ड फरीदाबाद के अंडरपास से तो फिर भी ट्रैफिक थोड़ा-थोड़ा चल रहा है लेकिन बुधवार को यह खबर लिखे जाने तक ग्रीन फील्ड और मेवला के अंडरपास से किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं गुजर पा रहा था। एफएमडीए की पहली बैठक में घोषणा की गई थी कि इस बार मॉनसून आने पर शहर का कोई अंडरपास पानी में नहीं डूबेगा। हम पानी निकालने के लिए अतिरिक्त मोटरें लगाएंगे। हालांकि ग्रीन फील्ड और मेवला अंडरपास के लिए पांच मोटरें पहले से ही लगी हुई हैं लेकिन इसके बावजूद स्थिति विकट है। दरअसल, मोटर खरीदने के नाम पर ही एफएमडीए में घपलेबाजी हो रही है। अधिकारी मोटर सप्लाई करने वाली फर्मों से कमीशन ज्यादा मांग रहे हैं। जबकि फर्मों का कहना है कि मोटा कमीशन देने पर मोटरें कम क्षमता की लगेंगी और पानी निकल नहीं पाएगा। यह जांच का विषय है कि पहले से लगी पांच मोटरें क्या क्षमता के हिसाब से चल रही हैं या उन्हें कम क्षमता के हिसाब से लगाया गया है। फरीदाबाद के नागरिक चाहें तो अपने इंजीनियरों की कमेटी बनाकर इस तरह की जांच करवाकर आम जनता और सरकार के सामने तथ्य रख सकते हैं। फरीदाबाद में नागरिकों का कोई प्रेशर ग्रुप नहीं होने के वजह से इस तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं।

सर्वोदय और केदार अस्पताल पर कार्रवाई कब होगी डीसी साहब

अस्पतालों के खिलाफ सीएम विंडो पर ढेरों शिकायतें, जांच के बावजूद कार्रवाई नहीं

.मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबादः कोविड 19 की दूसरी लहर के दौरान शहर के तमाम अस्पतालों ने मरीजों को जमकर लूटा। बहुत शोर मचने पर 12 मई 2021 को जिला मैजिस्ट्रेट यानी डीसी फरीदाबाद यशपाल यादव ने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में तमाम इलाकों के इंसीडेंट कमांडर, संबंधित इलाके के एसीपी और संबंधित इलाके के एसएमओ रखे गए। ये आदेश यशपाल यादव ने बतौर डीएम जारी किए थे। इस आदेश की कानूनी वैधता थी। डीएम ने इस कमेटी से कहा था कि जिन भी प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ ज्यादा फीस वसूलने और अन्य हथकंडे अपनाने पर शिकायतें आई हैं, उनकी जांच की जाए। इस कमेटी के जिम्मे सीएम विंडो पर इस संबंध में आई शिकायतें भी शामिल की गईं।

कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा

अकेले सीएम विंडो पर शहर के अस्पतालों के खिलाफ सैकड़ों शिकायतें पहुंचीं। लेकिन या तो उन शिकायतों को आगे फॉरवर्ड नहीं किया गया या फिर उन्हें किसी वजह से दबा दिया गया। शहर के एशियन अस्पताल, मेट्रो अस्पताल, फोर्टिस अस्पताल, सर्वोदय अस्पताल, केदार अस्पताल, डीएम अस्पताल, अर्श अस्पताल, संतोष अस्पताल समेत अनगिनत अस्पतालों के खिलाफ शिकायतें आईं। लेकिन अभी तक कमेटी ने किसी भी अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं की।

हाल ही में इस कमेटी ने सीएम विंडो पर आई राम दुलारी की शिकायत पर सर्वोदय अस्पताल को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए बुलाया था। सीएम विंडो से यह शिकायत सिविल सर्जन फरीदाबाद को मिली और वहां से फिर कमेटी के सदस्यों को इसे भेजा गया। राम दुलारी ने सीएम विंडो पर की गई शिकायत में सर्वोदय अस्पताल सेक्टर 8 फरीदाबाद पर मेडिकल बिलो में हेराफेरी का आरोप लगाया था। राम दुलारी का कहना था कि सरकार की ओर से तमाम टेस्ट की जो फीस कोविड 19 के दौरान तय की गई थी, सर्वोदय अस्पताल ने उसकी धज्जियां उड़ा दीं। इसलिए इस अस्पताल की जांच कराई जाए।

सेक्टर 16 में रहने वाले एक बुजुर्ग ने सीएम विंडो पर केदार अस्पताल एनएच 3 के खिलाफ सख्त शिकायत की। मजदूर मोर्चा के पास शिकायतकर्ता की शिकायत की कॉपी और सीएम विंडो पर लगाई गई शिकायत की फोटोकॉपी मौजूद है। शिकायतकर्ता ने लिखा था कि उन्हें कोरोना होने पर 20 अप्रैल 2021 को केदार अस्पताल 3बी/3 फरीदाबाद में भर्ती होना पड़ा। 29 अप्रैल 11 बजे पूर्वाह्न उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। लेकिन इस दौरान मरीज यानी शिकायतकर्ता से 4 लाख 5 हजार रुपये

इलाज के नाम पर वसूले गए। हालांकि इस दौरान न उन्हें आईसीयू में रखा गया, न वेंटिलेटर पर रखा गया। उन्हें अस्पताल के जनरल वॉर्ड में रखा गया।

शिकायतकर्ता ने डीसी से इस संबंध में 3 जून को शिकायत की थी। डीसी दफ्तर से एसडीएम बडखल को इस मामले की जांच के लिए लिखा गया। लेकिन एसडीएम ने आजतक न तो कोई जांच की और न कोई कार्रवाई हुई। बुजुर्ग शिकायतकर्ता का कहना है कि अस्पताल वालों को राजनीतिक रसूख हासिल है, इसलिए उनके जैसे बुजुर्गों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अस्पताल अभी भी मामले को रफा-दफा करने में जुटा हुआ है।

बड़े अस्पतालों को संरक्षण क्यों

ऐसा नहीं कि जिला प्रशासन के पास शिकायत सिर्फ सर्वोदय और केदार अस्पताल की पहुंची। प्रशासन के पास एशियन अस्पताल, फोर्टिस, डीएम अस्पताल, मेट्रो अस्पताल की भी शिकायत पहुंची हुई है। लेकिन प्रशासन ने इन बड़े अस्पतालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया।

एनआईटी के एक अस्पताल के खिलाफ पैसा वसूलने की शिकायतें तो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थीं लेकिन प्रशासनिक अधिकारी उस मामले को पी गए। खुद डीसी फरीदाबाद ने बल्लभगढ़ के एक अस्पताल में अवैध कोविड सेंटर पकड़ा था लेकिन उस अस्पताल पर भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले पाया।